जवाहर लाल गुप्ता और आशुतोष मोहनता, जे.जे के समक्ष

रोहित दत्ता और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ – उत्तरदाता

C.W.P. 1999 का No.15897

17 जुलाई, 2001

भारत का संविधान, 1950 – *अनुच्छेद* 14 और 226 – *सरकारी, निजी वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अधिकारियों के लिए विशेष रूप से* M.B.A. *अंशकालिक/शाम का पाठ्यक्रम आयोजित करने वाला विश्वविद्यालय- सिंडिकेट द्वारा उक्त पाठ्यक्रम के संबंध में शुल्क की दर में संशोधन*-M.B.A. *छात्रों (सुबह) के संबंध में शुल्क की दर* M.BA *छात्रों (*Evening) *की तुलना में बहुत कम है। - डिफरेंशियल ट्रीटमेंट-* M.BA *अंशकालिक/शाम की कक्षाएं में प्रवेश के लिए केवल प्रशासनिक या कार्यकारी पदों को धारण करने वाले व्यक्ति योग्य। -ऐसे उम्मीदवार जो पर्याप्त मात्रा में वेतन प्राप्त करते हैं-शुल्क की दर में विभेदक व्यवहार उम्मीदवार की आय के आधार पर एक तर्कसंगत है-विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम की एकीकृत प्रकृति के बावजूद शुल्क को संशोधित करने और बाद के वर्ष के लिए एक अलग मानदंड लागू करने का अधिकार है-छात्रों पर सिंडिकेट निर्णय बाध्यकारी -शुल्क को संशोधित करने में विश्वविद्यालय की कार्रवाई न तो मनमाना है और न ही भेदभाव के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है-छात्र पहले से ही* M.BA *अंशकालिक पाठ्यक्रम में भर्ती हैं संशोधित दर पर शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य है।*

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता प्रबंधक, कार्यपालक और निदेशक आदि के वरिष्ठ पदों पर हैं। उन्हें काफी वेतन मिल रहा है। वे गरीब नहीं हैं। न ही गरीब माता-पिता पर निर्भर। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता एक अलग वर्ग हैं। शुल्क की दर में अंतर, उम्मीदवार की आय के आधार पर एक तर्क है। इसका उत्पादन संसाधनों के उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध है। इस स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय मनमाने ढंग से याचिकाकर्ताओं के साथ अन्य छात्रों से अलग व्यवहार कर रहा है। प्राधिकरण का निर्णय कानून और समानता में पूरी तरह से उचित है। यह भेदभाव की बुराई से पीड़ित नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। इस प्रकार, विवादित निर्णय को अनुच्छेद 14 के विपरीत होने के कारण रद्द नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 20 और 26)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि पाठ्यक्रम की एकीकृत प्रकृति के बावजूद छात्र "विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा समय-समय पर निर्धारित" शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। इस प्रकार, सिंडिकेट के पास किसी भी समय दरों को संशोधित करने की शक्ति है। सिंडिकेट का निर्णय छात्रों के लिए बाध्यकारी है। फीस संशोधन का मामला काफी समय से विश्वविद्यालय के पास लंबित था। 30 जुलाई, 1999 को हुई बैठक में सिंडिकेट द्वारा दर को संशोधित करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार छात्रों को वर्ष 1999-2000 के दौरान पूरे सत्र के लिए संशोधित दर पर शुल्क

का भुगतान करने के लिए कहा गया है। निर्णय किसी भी तरह से पूर्वव्यापी रूप से काम नहीं करता है।

(पैरा 36)

आर.के. मलिक, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता* के लिए।

अनुपम गुप्ता, अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, जे.

(1) इन दो रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि 3 वर्षीय अंशकालिक एमबीए पाठ्यक्रम में भर्ती अधिकारियों के लिए शुल्क बढ़ाने में विश्वविद्यालय की कार्रवाई मनमाना, अवैध अन्यायपूर्ण, अनुचित और असंवैधानिक है। क्या ऐसा है?

(2) वकील ने 1999 का C.W.P. नं.15897 में तथ्यों और अभिवचनों का उल्लेख किया है। इन पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

(3) पंजाब विश्वविद्यालय मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के लिए पाठ्यक्रम संचालित करता है। इनमें से एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। दूसरे को अंशकालिक पाठ्यक्रम कहा जाता है जो शाम को आयोजित किया जाता है। बाद वाला पाठ्यक्रम विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए आयोजित किया जाता है जिनके पास योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रतिष्ठान में कम से कम दो साल का पूर्णकालिक कार्यकारी अनुभव है। यहां तक कि अखिल भारतीय, राज्य प्रशासनिक/तकनीकी सेवाओं और रक्षा कार्मिक के सदस्य भी प्रशासनिक पदों पर "कम से कम 2 साल के कार्यकारी अनुभव के साथ" आसीन होने के पात्र हैं। इन उम्मीदवारों के लिए, "संगठनात्मक प्रायोजन आवश्यक है"।

(4) C.W.P नं. 1999 के 15897 में याचिकाकर्ता ने वर्ष 1997 और 1998 में पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। 2000 के C.W.P. नं. 3811 में याचिकाकर्ता को वर्ष 1999 में भर्ती किया गया था।

(5) याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि शुरू में विश्वविद्यालय 1,080 रुपये प्रति वर्ष की दर से शुल्क ले रहा था। । हालांकि, 27 अगस्त, 1999 को सिंडिकेट ने शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया और इसे बढ़ाकर रु 955 प्रति माह कर दिया। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दो वर्षीय पाठ्यक्रम में सुबह शामिल होने वाले छात्रों से बहुत कम दर पर शुल्क लिया जा रहा है। यहां तक कि LL.B और M.A. पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिए छात्रों से कम दर पर

शुल्क लिया जा रहा है। इस प्रकार, M.B.A. (शाम के पाठ्यक्रम) में प्रवेश लेने वाले छात्र के लिए शुल्क की उच्च दर लागू करने में विश्वविद्यालय का कार्य मनमाना और अनुचित है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि फीस की बढ़ी हुई दर सिंडिकेट के निर्णय के बाद पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर लागू की जा सकती है, न कि उन लोगों पर जो पहले से ही पढ़ रहे थे। इस आधार पर, याचिकाकर्ता प्रार्थना करते हैं कि संशोधित दर पर शुल्क लेने के विश्वविद्यालय के निर्णय को रद्द कर दिया जाए।

(6) विश्वविद्यालय दावे का विरोध करता है। इसमें कहा गया है कि "एमबीए अंशकालिक/शाम के पाठ्यक्रम में भर्ती होने वाले व्यक्ति सभी स्वतंत्र हैं, जो कार्यकारी पदों पर हैं।" "एमबीए इवनिंग/पार्ट टाइम कोर्स के छात्रों और एमबीए मॉर्निंग कोर्स के छात्रों के बीच स्थिति का एक मौलिक और भौतिक अंतर है और एमबीए मॉर्निंग कोर्स के छात्र आम तौर पर अन्य विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों की तरह अपने माता-पिता/अभिभावकों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। दूसरी ओर, एमबीए ईविंग/अंशकालिक पाठ्यक्रम के छात्र स्वतंत्र हैं, कमाते हैं, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यकारी पदों पर हैं या अखिल भारतीय या राज्य प्रशासनिक/तकनीकी सेवाओं के सदस्य हैं। इस आधार पर, यह कहा जाता है कि "एमबीए इवनिंग कोर्स के छात्रों की वित्तीय स्थिति या भुगतान क्षमता मॉर्निंग कोर्स के छात्रों की तुलना में कहीं बेहतर और अधिक है जो पूरी तरह से अपने माता-पिता पर निर्भर हैं।" विश्वविद्यालय वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। 'शिक्षा की मात्रा और गुणवत्ता को बनाए रखने और बढ़ावा देने' में सक्षम होने के लिए संसाधन उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, फीस को संशोधित करने की आवश्यकता अनिवार्य थी।

(7) जहां तक अन्य पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क की दर के आधार पर भेदभाव के आरोप का संबंध है, यह बताया गया है कि "विश्वविद्यालय M.A (समाजशास्त्र) के लिए कोई शाम का पाठ्यक्रम या कक्षाएं नहीं चलाता है। LL.B के बारे में बेशक, यह बताया गया है कि मॉर्निंग और इवनिंग क्लास के बीच कोई अंतर नहीं है जो एक ही पाठ्यक्रम की केवल दो पालियां हैं"। शाम की कक्षाएं केवल "अधिकारियों" तक ही सीमित नहीं हैं।

(8) यह भी बताया गया है कि विवादित निर्णय लेने से पहले विश्वविद्यालय द्वारा इस मामले पर विचार किया गया था। वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए दिसंबर, 1998 में एक समिति का गठन किया गया था। मौजूदा शुल्क संरचना की जांच की गई। इस मामले पर गहन विचार-विमर्श के बाद सिंडिकेट द्वारा विवादित निर्णय लिया गया था।

(9) इन प्राक्कल्पनाओं पर, विश्वविद्यालय का कहना है कि कार्रवाई कानूनी और वैध है।

(10) श्री आर.के. मलिक, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले का तर्क दिया, ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय की कार्रवाई मनमाना और भेदभावपूर्ण है। विश्वविद्यालय उन छात्रों पर शुल्क की संशोधित दर लागू नहीं कर सकता है जिन्होंने पहले ही प्रवेश ले लिया था। उन्नी कृष्णन, J.P. और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य[1] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को यह तर्क देने के लिए लागू किया गया था कि 100% सीटों को विश्वविद्यालय द्वारा "भुगतान" सीटों में परिवर्तित कर दिया गया था।

(11) याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए दावे का श्री अनुपम गुप्ता ने विरोध किया जिन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता एक अलग वर्ग बनाते हैं। निर्णय न्यायसंगत और निष्पक्ष था। उचित विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया था। यह विश्वविद्यालय को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुरूप है। इस प्रकार, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया गया।

(12) विचार के लिए उत्पन्न होने वाले दो प्रश्न हैं: -

(1)क्या विश्वविद्यालय की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है?

(2)क्या याचिकाकर्ता सिंडिकेट के निर्णय के अनुसार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं?

1 के बारे में

13. शिक्षा जरूरी है। यह जीवन के अधिकार का हिस्सा है। राज्य का दायित्व है कि वह शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करे। हालाँकि, यह दायित्व आर्थिक क्षमता से सीमित है। उच्च शिक्षा के मामले में ऐसा अधिक होता है। नतीजतन, राज्य और यहां तक कि एक विश्वविद्यालय के लिए भी शुल्क आदि के भुगतान के लिए शर्तें निर्धारित करने की अनुमति है। ताकि वह खर्च के कम से कम एक हिस्से को पूरा कर सके जो वह वहन करता है।

14. वर्तमान मामले में, यह विशेष रूप से बताया गया है कि विश्वविद्यालय वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। वास्तव में, यह एक राष्ट्रीय घटना है।

[1] 1993 (1) SLR 743

जबकि मजदूरी बढ़ रही है और शासन की लागत बढ़ रही है, संसाधन सीमित हैं। इस स्थिति में, स्कूल, राज्य और विश्वविद्यालय छात्रों को लगभग मुफ्त शिक्षा प्रदान करना जारी नहीं रख सकते हैं। आवश्यक रूप से, संसाधन उत्पन्न करने होंगे। तभी उच्च शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं और जारी रखी जा सकती हैं।

15. विश्वविद्यालय द्वारा दायर जवाब दावा के अवलोकन से पता चलता है कि दिसंबर, 1998 में शुल्क संरचना की जांच करने और "संशोधित शुल्क की सिफारिश करने" के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति की बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति जवाब दावा के साथ अनुलग्नक R1 के रूप में प्रस्तुत की गई है। इन कार्यवृत्तों के अवलोकन से संकेत मिलता है कि समिति में 16 व्यक्ति शामिल थे। विश्वविद्यालय शिक्षण के डीन इसके अध्यक्ष थे। पंजाब विश्वविद्यालय के अध्येता; डीन, कॉलेज विकास परिषद; विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य सदस्य थे। समिति ने पाया कि मौजूदा शुल्क "बहुत कम था"। "सरकार के बार-बार आग्रह" को देखते हुए "धन की भुखमरी को कम करने के लिए संसाधन" उत्पन्न करना आवश्यक था। इस प्रकार, समिति ने संशोधित शुल्क संरचना की सिफारिश की थी। इसने आगे सिफारिश की थी कि इसकी हर साल समीक्षा की जाए।

16. 17 मार्च, 1999 को हुई बैठक में सिंडिकेट द्वारा इस मामले पर विचार किया गया था। सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। कुलपति ने बताया था कि जब आय का स्तर चारों ओर बढ़ गया था, तो शुल्क अछूता नहीं रह सकता था। वर्तमान में, छात्र अच्छी तरह से रह रहे थे। वे अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक खर्च कर रहे थे। शिक्षा, बुनियादी ढांचे और उपकरणों की लागत कई गुना बढ़ गई थी। मौजूदा शुल्क स्तर को बनाए रखने के लिए कोई नैतिक या कानूनी औचित्य नहीं था। जमीनी हकीकत पर ध्यान देना जरूरी था। जबकि "सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उच्च शिक्षा के प्रति अपने

दायित्व को पूरा करना चाहिए", फीस "मामूली स्तर पर" नहीं रह सकती थी। यह भी बताया गया कि फीस बढ़ाने से विश्वविद्यालय 10% से अधिक नहीं कमाने वाला है।

17. कुलपति द्वारा दिए गए अच्छे कारणों के बावजूद सिंडिकेट ने मामले को पुनर्विचार के लिए समिति को भेजने का निर्णय लिया था। छात्रों के प्रतिनिधियों सहित नए सदस्यों को जोड़कर समिति के गठन में बदलाव किया गया। विश्वविद्यालय छात्र परिषद के अध्यक्ष और सचिव सहित 21 सदस्यों वाली समिति द्वारा इस मामले पर पुनर्विचार किया गया था। समिति ने एक चार्ट तैयार किया था जिसमें गुरनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर और पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला में शुल्क की तुलनात्मक दरों का संकेत दिया गया था। इसने अपने द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क की दर में संशोधन का प्रस्ताव किया। 30 जुलाई, 1999 को हुई बैठक में सिंडिकेट द्वारा समिति की सिफारिश पर विचार किया गया था। संबद्ध कॉलेजों के मामले में 1 मई, 1999 से और विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के मामले में 1 जून, 1999 से संशोधित दरों को मंजूरी दी गई थी।

18. घटनाओं के क्रम को देखने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उचित विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया था। दरों का संशोधन केवल एक विकल्प नहीं था, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता थी। विश्वविद्यालय को "शिक्षा की मात्रा और गुणवत्ता" को बनाए रखने और बढ़ावा देने में सक्षम बनाने के लिए यह आवश्यक था। यह निर्णय किसी भी तरह से मनमाना या अनुचित नहीं था।

19. श्री मलिक ने तर्क दिया कि यह कार्रवाई भेदभावपूर्ण है क्योंकि विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क की विभिन्न दरें निर्धारित की गई थीं। विशेष रूप से, वकील ने प्रस्तुत किया कि सुबह में एमबीए छात्रों से ली जाने वाली फीस की दर शाम के पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले एमबीए छात्रों के लिए निर्धारित दर से बहुत कम है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यहां तक कि LL.B में शाम की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों से शुल्क की दर भी बहुत कम थी। इस प्रकार, कार्रवाई को भेदभाव के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ा। क्या ऐसा है?

20. माना जाता है कि एमबीए इवनिंग कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्र स्वतंत्र रूप से कमाने वाले होते हैं। वे सरकारी या निजी संगठनों में कार्यकारी पदों पर रहते हैं। इस संबंध में अपने दावे का समर्थन करने के लिए विश्वविद्यालय ने सत्र 1999-2000 के दौरान शाम के पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले छात्रों की एक सूची तैयार की है। उनके द्वारा धारण किए गए पदों और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्राप्त वेतन की दरों को जवाब दावे के साथ अनुलग्नक R-10 में दस्तावेज़ में इंगित किया गया है। उसके अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता प्रबंधक, कार्यकारी और निदेशक आदि के वरिष्ठ पदों पर हैं। उन्हें काफी वेतन मिल रहा है। वे गरीब नहीं हैं। न ही गरीब माता-पिता पर निर्भर। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता एक अलग वर्ग हैं। शुल्क की दर में अंतर के लिए उम्मीदवार की आय का आधार एक तर्क है। संसाधन उत्पन्न करने के उद्देश्य के साथ इसका एक उचित संबंध है। इस स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय मनमाने ढंग से याचिकाकर्ताओं के साथ

अन्य छात्रों से अलग व्यवहार कर रहा है। प्राधिकरण का निर्णय कानून और समानता में पूरी तरह से उचित है।

21. यह निस्संदेह सत्य है कि विश्वविद्यालय द्वारा सुबह पढ़ने वाले एम. बी. ए. छात्रों के संबंध में निर्धारित फीस की दर शाम के सत्र में भर्ती होने वालों की तुलना में बहुत कम है। हालाँकि, विभेदक उपचार का भी एक अच्छा आधार है। यह स्वीकृत स्थिति है कि केवल दो साल के अनुभव वाले प्रशासनिक या कार्यकारी पदों पर आसीन व्यक्ति ही शाम की कक्षाओं में एमबीए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। यहाँ तक कि संगठनात्मक प्रायोजन भी आवश्यक है। जो उम्मीदवार विभिन्न वाणिज्यिक या सरकारी संगठनों की सेवा कर रहे हैं, वे अपनी दक्षता और करियर प्रॉस्पेक्टस में सुधार के लिए इन पाठ्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। चीजों की प्रकृति में, उन्हें विश्वविद्यालय के वित्तीय बोझ का एक हिस्सा वहन करना चाहिए। विश्वविद्यालय ठीक यही हासिल करना चाहता है।

22. श्री मलिक ने तर्क दिया कि कानून की डिग्री या "मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन" की डिग्री के लिए शाम की कक्षाओं में शामिल होने वाले व्यक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार, उम्मीदवारों की दो श्रेणियों से शुल्क में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर, विश्वविद्यालय के विद्वान वकील श्री अनुपम गुप्ता ने बताया कि "जहां तक LL.B पाठ्यक्रम का संबंध है, सुबह और शाम की कक्षाओं के बीच कोई अंतर नहीं है जो एक ही पाठ्यक्रम की केवल दो पालियां हैं।

23. यह स्वीकृत स्थिति है कि एमबीए सुबह और शाम के पाठ्यक्रमों की अवधि अलग है। जबकि मॉर्निंग कोर्स दो साल का होता है, शाम के छात्र तीन साल तक अध्ययन करने के बाद अंतिम परीक्षा के लिए

अर्हता प्राप्त करते हैं। यह अंतर LL.B के छात्रों के मामले में मौजूद नहीं है। फिर भी, किसी व्यक्ति के लिए LL.B ईविंग कोर्स में प्रवेश के लिए कार्यकारी पद धारण करना आवश्यक नहीं है। यहाँ तक कि एक चाय विक्रेता भी पाठ्यक्रम में शामिल हो सकता है। LL.B. और एमबीए पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की आर्थिक स्थिति में स्पष्ट अंतर है। प्रवेश के लिए पात्रता की शर्त में यह आवश्यक अंतर विश्वविद्यालय की कार्रवाई को पूरी तरह से उचित ठहराता है।

24. एक अन्य तथ्य जो उल्लेख करने योग्य है, वह यह है कि शुल्क निर्धारण के मामले में प्राधिकरण को विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है। छात्रों की संख्या, बुनियादी ढांचे की प्रकृति और आवश्यक शिक्षकों की संख्या कुछ प्रासंगिक इनपुट हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐसे पाठ्यक्रम में जहां केवल कुछ छात्र अध्ययन कर रहे हैं, प्रति छात्र लागत अधिक होगी क्योंकि सभी शिक्षकों को भुगतान करना होगा लेकिन एकत्र की गई फीस की राशि कम होगी। इसके विपरीत, जब संख्या अधिक है, तो प्रति व्यक्ति लागत कम होनी चाहिए।

25. यह स्वीकृत स्थिति है कि विधि में शाम की कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या एमबीए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या से बहुत अधिक है। इस स्थिति में, वह लागत जो विश्वविद्यालय प्रत्येक LL.B छात्र पर वहन करता है, एम. बी. ए. छात्र पर खर्च की गई राशि की तुलना में काफी कम है। इसी तरह, विज्ञान विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों के मामले में, प्रयोगशालाओं आदि की सुविधाएं प्रदान करने पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, शुल्क के निर्धारण के लिए एक फुलप्रूफ या सार्वभौमिक तरीका नहीं हो सकता

है। मौजूदा चर को देखते हुए, न्यायालय गणितीय या वैज्ञानिक सटीकता पर जोर नहीं दे सकता है। कुछ मतभेद अपरिहार्य हैं। रिट-कोर्ट तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब कार्रवाई मनमाना होती है कि । अन्यथा नहीं। वर्तमान मामले में, हम संतुष्ट हैं कि हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनाया गया है।

26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि फीस को संशोधित करने में विश्वविद्यालय की कार्रवाई मनमाना या अनुचित नहीं है। यह भेदभाव की बुराई से पीड़ित नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। इस प्रकार, विवादित निर्णय को अनुच्छेद 14 के विपरीत होने के कारण रद्द नहीं किया जा सकता है।

27. प्रथम प्रश्न का उत्तर तदनुसार याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध दिया जाता है।

2 के बारे में

28. श्री मलिक ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अलग-अलग समय पर पाठ्यक्रम में शामिल हुए थे। इस प्रकार, वे उन दरों पर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं जो संबंधित वर्षों में प्रवेश के समय मौजूद थीं। शुल्क की दरों का बाद में संशोधन उन पर लागू नहीं किया जा सकता है। यह आदेश के पूर्वव्यापी आवेदन के बराबर होगा। ऐसा है?

29. पूछे जाने के बावजूद, विद्वान वकील यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर किसी भी चीज़ का उल्लेख करने में असमर्थ थे कि विश्वविद्यालय ने कभी वादा किया था कि पाठ्यक्रम पूरा होने तक शुल्क की दरें अपरिवर्तित रहेंगी। इसके अलावा, हम पाते हैं कि विश्वविद्यालय ने अपने नियमों और विनियमों को एक कैलेंडर के

रूप में प्रकाशित किया। यह कैलेंडर तीन खंडों में है। खंड-II में विनियम शामिल हैं। बहुत हद तक खंड-II के शुरुआती पृष्ठ पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ हैं। ये निम्नानुसार हैंः -

> "1. सभी प्रवेश/परीक्षा और अन्य शुल्क आदि जैसा कि इस कैलेंडर, खंड में विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न अध्यायों में दिया गया है, शुल्क/निधि/प्रभार आदि की संशोधित दरों द्वारा प्रतिस्थापित माना जाएगा। जैसा कि अध्याय संख्या X में दिया गया है।
>
> 2. अब से, सभी प्रवेश/परीक्षा/अन्य सभी शुल्क, निधि और शुल्क विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा समय-समय पर तय किए जाने के अनुसार होंगे। (जोर दिया गया)
>
> 3. वर्तमान में लागू शुल्कों, निधियों और प्रभारों के लिए, कृपया इस कैलेंडर खंड के पृष्ठ 508-514 पर अध्याय संख्या X देखें।

30 इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय ने शुल्क आदि को समय-समय पर संशोधित करने का अधिकार स्पष्ट रूप से सुरक्षित रखा है। इस संबंध में निर्णय विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा लिया जाना है। वर्तमान मामले में ठीक यही हुआ है। सिंडिकेट ने शुल्क की दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय कार्यालय द्वारा तदनुसार कार्रवाई की गई है।

31 एक अन्य तथ्य जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि विनियमों की प्रयोज्यता के संबंध में भी विश्वविद्यालय द्वारा एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है। यह निम्नानुसार प्रदान किया गया हैः-

"एक से अधिक शैक्षणिक वर्ष में फैले पाठ्यक्रम की एकीकृत प्रकृति के बावजूद, एक छात्र के पाठ्यक्रम में शामिल होने के समय लागू विनियम केवल शैक्षणिक वर्ष के दौरान या अंत में आयोजित परीक्षाओं के लिए लागू होंगे। इन विनियमों में कुछ भी विश्वविद्यालय को बाद में विनियमों में संशोधन करने से रोकने वाला नहीं समझा जाएगा और संशोधित विनियम, यदि कोई हो, सभी छात्रों पर लागू होंगे, चाहे वे पुराने हों या नए।“

32 इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब एक वैधानिक विनियमन द्वारा एक प्रावधान किया गया है, तब भी यह केवल वर्ष के दौरान ही लागू होता है। विश्वविद्यालय के पास पाठ्यक्रम की एकीकृत प्रकृति के बावजूद बाद के वर्ष के लिए एक अलग मानदंड लागू करने की शक्ति है।

33 विश्वविद्यालय समय-समय पर "सूचना की हस्तपुस्तिका" प्रकाशित करता है। छात्रों से ली जाने वाली फीस का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र को निर्धारित दर पर शुल्क का भुगतान करना होगा।

34 वर्ष 1999 के लिए सूचना पुस्तिका में, एमबीए शाम के पाठ्यक्रम के लिए शुल्क की दर 1,000 रुपये प्रति माह की दर से निर्धारित की गई है। पृष्ठ XXX पर यह भी प्रदान किया गया है कि ट्यूशन शुल्क 12 महीने के लिए जून से मई तक लिया जाएगा। प्रत्येक छात्र को दो किस्तों यानी एक प्रवेश के समय और दूसरा 10 नवंबर से 30 नवंबर के दौरान, में ट्यूशन और अन्य शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। । विश्वविद्यालय तदनुसार शुल्क की मांग कर रहा है। इसकी कार्रवाई किसी भी नियम या विनियमन का उल्लंघन नहीं करती है।

35 श्री मलिक ने तर्क दिया कि पहले से ही अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए संशोधित दर को लागू करना शुल्क की दर के पूर्वव्यापी संशोधन के बराबर है।

36 हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सबसे पहले, यह स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम की एकीकृत प्रकृति के बावजूद छात्र "विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा समय-समय पर तय किए गए" शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। इस प्रकार, सिंडिकेट के पास किसी भी समय दरों को संशोधित करने की शक्ति है। सिंडिकेट का निर्णय छात्रों के लिए बाध्यकारी है। दूसरा, यह स्वीकृत स्थिति है कि फीस में संशोधन का मामला काफी समय से विश्वविद्यालय के पास लंबित था। 30 जुलाई, 1999 को हुई बैठक में सिंडिकेट द्वारा दर को संशोधित करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, छात्रों को वर्ष 1999-2000 के दौरान पूर्ण सत्र के लिए संशोधित दर पर शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया है। निर्णय किसी भी तरह से पूर्वव्यापी रूप से काम नहीं करता है।

37 यह उल्लेख किया जा सकता है कि थोड़ी अलग स्थिति में, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ बनाम सुभाष चंदर और एक अन्य[2] मामले में पूर्वव्यापीता का तर्क उठाया गया था- अनुग्रह अंक प्रदान करने के संबंध में एक विनियमन के संशोधन से निपटने के दौरान, यह माना गया था कि एक उम्मीदवार "उस समय मौजूद विनियमों द्वारा शासित होना जारी रखेगा जब वह अध्ययन के वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल हुआ था" हालांकि, इस विचार को पंजाब विश्वविद्यालय बनाम सुभाष चंदर और अन्य[3] में सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप्स द्वारा

[2] 1976 PLR 920
[3] AIR 1984 SC 1415

उलट दिया गया था। यह माना जाता है कि जब विश्वविद्यालय ने नियमों को बदला तो कोई "पूर्वव्यापीता का तत्व" नहीं था। यह भी कहा गया कि "1965 में उनके प्रवेश के समय उनसे कोई वादा नहीं किया गया था या ऐसा नहीं माना जा सकता कि कोई वादा किया गया कि किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए या अनुग्रह अंकों के पुरस्कार के लिए आवश्यक अंकों के प्रतिशत के संबंध में नियम या विनियमन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा...."

38 इस प्रकार, दूसरे प्रश्न का भी उत्तर याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध दिया जाता है।

39 कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया था।

40 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। नतीजतन, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता उनसे देय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। उन्हें दो महीने के भीतर आवश्यक कार्य करना चाहिए। विफलता के मामले में, विश्वविद्यालय कानून के अनुसार आगे बढ़ने का हकदार होगा। याचिकाएं खारिज की जाती हैं। इन परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

S.C.K.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता गुप्ता

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
बिलासपुर,यमुनानगर

जवाहर लाल गुप्ता और आशुतोष मोहनता से पहले, जे.जे
जस्बीर कौर और & *ANOTHER, – याचिकाकर्ता*

बनाम

पंजाब राज्य औद्योगिक विकास
निगम लि. तथा *ANOTHER, – उत्तरदाताओं*

C.W.P. 1999 की संख्या 6457

23 अगस्त 2001

का संविधान भारत, 1950 – कला. 226 – राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 – S. 29 – ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया –धारा 29 – के तहत कार्रवाई करने वाला निगम ऋणदाता और प्रतिभूति गुण – स्कोप ऑफ एस. 29 – निगम पूरी तरह से कब्जे में लेने के लिए उचित है। गिरवी / गिरवी रखी गई संपत्तियां-

---

(३) आकाशवाणी १ ९ 3४ एससी १४१५